एशियाई विकास बैंक की 39वीं वार्षिक आम बैठक में प्रधान मंत्री का भाषण

5 मई, 2006
हैदराबाद

मैं आप सबका भारत में स्वागत करके बहुत प्रसन्न हूं। हमें इस बात में गौरव महसूस हो रहा है कि एशियाई विकास बैंक की 39वीं वार्षिक आम बैठक ऐतिहासिक और सुन्दर शहर हैदराबाद में हो रही है। मैं आप सबको भारत की जनता और भारत सरकार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हैदराबाद में आपका प्रवास आपके लिए यादगार बन जाएगा और आपके विचार-विमर्श और निष्कर्ष उपयोगी और सार्थक होंगे।

भारत को एशियाई विकास बैंक का संस्थापक सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। एशियाई विकास बैंक के साथ मिल कर काम करने पर हमें गर्व है और विकास में हमारा सक्रिय भागीदार बनने के लिए हम बैंक के आभारी हैं। आज जब हम अपनी विकास प्रक्रिया में और तेजी लाना चाहते हैं तो हम एशियाई विकास बैंक के साथ और निकट सहयोग के संबंधों की आशा करते हैं। हम एशियाई विकास बैंक को मजबूत बनाने के प्रति अपना संकल्प व्यक्त करते हैं ताकि यह इस क्षेत्र में विकास और बेहतर प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन सके।

हालांकि एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय बैंक है, लेकिन विश्व में एशिया की बढती प्रतिष्ठा से यह बैंक विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण हो गया है। एशियाई वित्तीय संकट से निपटने में एशियाई बैंक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और एशिया में आए सुनामी संकट, बड़े-बड़े भूकंपो और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को राहत पहुंचाने में बैंक ने सराहनीय योगदान दिया है। बुनियादी ढांचों के लिए धन राशि जुटाने में एशियाई विकास बैंक की विशेषज्ञता को भारत बहुत मूल्यवान समझता है। एशियाई बैंक ने ऋणों के माध्यम से भारत की कई बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है। मुझे इस बात पर बड़ी प्रसन्न्ता है कि हमारे देश के दूर-दराज के राज्य- जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों को भी एशियाई विकास बैंक की आर्थिक सहायता से लाभ मिला है।

अगले कुछ वर्षों में भारत को बुनियादी ढांचों के विकास के लिए डेढ खरब डालर से अधिक राशि की आवश्यकता होगी। एशियाई विकास बैंक ने सार्वजनिक परिवहन, बिजली और शहरी बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है। लेकिन मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि एशियाई विकास बैंक अब जल संसाधनों को पुनःस्थापित करने, पयर्टन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं जुटाने और कृषि संबंधी कारोबार बढ़ाने जैसे क्षेत्रों के लिए सहायता उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है। हाल के वर्षों में हमारे पूंजी निवेश की दर हमारे सकल घरेलू उत्पाद के 31 प्रतिशत तक पहुंच गई है। आगे आने वाले वर्षों में पूंजी निवेश की दर में हम और बढ़ोत्तरी की उम्मीद करते हैं और भारत में विदेशी पूंजी निवेश की दर में भी वृद्धि की हमें आशा है।

बहनो और भाईयो,

भारत के लिए एशिया की खुशहाली और स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वी देशों के लिए 'Look East' की अपनी नीति से हमने क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के प्रति फिर से वचनबद्धता दोहराई है। इस नीति के जरिए विश्व के प्रति भारत के बदलते नजरिए की झलक मिलती है। इस नीति से हमें 1940 और 1950 के दशकों के समय के उन सूत्रों को फिर से जोड़नें में सहायता मिली है, जब हम नए एशिया के निर्माण में सक्रियता से लगे हुए थे। 'Look East' का स्वभाविक परिणाम यह है कि भारत में एशियाई देशों के साथ और अलग-अलग तौर पर पूर्व एशियाई देशों के साथ मिल कर काम करने की अपनी बचनबद्धता को दोहराया है। हम इस क्षेत्र के देशों के साथ मुक्त व्यापार और व्यापक आर्थिक सहयोग समझौतों के जरिए भारत को साझेदारी की व्यवस्था से जोड़ रहे हैं।

हमनें दक्षिण एशियाई देशों के क्षेत्रीय सहयोग संगठन-सार्क, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न किए हैं। आसियान देशों, जापान, चीन गण राज्य और दक्षिण कोरिया के साथ भी इसी तरह के समझौते करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। इन सब समझौतों के परिणाम स्वरूप अंततः पूरा एशिया एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बन सकता है, जिसमें सभी प्रमुख एशियाई अर्थ-व्यवस्थाएं शामिल होंगी और संभवतः आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल होंगे। एशियाई देशों का यह मुक्त व्यापार समझौता एशिया का भविष्य बन सकता है और मेरा विश्वास है कि इससे हमारी अर्थ-व्यवस्थाओं के विकास के लिए नए मार्ग प्रशस्त होंगे। एशियाई विकास बैंक एशिया में इस तरह की सम्मिलित आर्थिक व्यवस्था के

लाभों का अध्ययन भी कर सकता है। भारत का निश्चय भारत और आसियान देशों के बीच भागीदारी को व्यापक रूप देने का है, ताकि 21वीं शताब्दी वास्तविक तौर पर एशिया की शताब्दी बन सके।

अपने सामने इस लक्ष्य को रखते हुए हमने सीमा-शुल्क की दरों में कटौती करके अपनी नीतियों को उदार बनाने की दिशा में तेजी से काम किया है। इस समय लगभग साढ़े बारह प्रतिशत की जो अधिकतम दर है, वह आसियान देशों के बहुत करीब है। भारत ने नीति संबंधी अपनी घोषणा में कहा है कि वह सीमा शुल्क दरों को आसियान देशों के स्तर तक लायेगा। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में प्राकृतिक संपदा, तकनीकी क्षमता और वैज्ञानिक प्रतिभा का जो विशाल भंडार है, उसका विश्व व्याापीकरण के लिए उपयोग किया जा सकता है, न केवल राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए बल्कि समग्र विश्वव्यापी आर्थिक विकास के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है ।

बहनो और भाइयो,

हमारे क्षेत्र ने दिखा दिया है कि विश्वव्यापीकरण की चुनौतियों से निपटने की उसमें क्षमता है, लेकिन विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया में जो निहित अनिश्चितताएं हैं और उतार-चढ़ाव की जो आशंकाएं हैं उनके प्रति हमें सचेत रहना होगा। 1997 में आये एशियाई वित्तीय संकट ने ऐसे देशों को प्रभावित किया, जिन्होंने अद्भुत तरीके से अपनी अर्थ-व्यवस्थाओं का विकास किया था, जिसे देख कर दूसरे देश ईर्ष्या करते थे। अचानक पैदा हुए इस वित्तीय संकट और इसकी गंभीरता ने विश्वव्यापीकरण में दुनिया भर के देशों के विश्वास को हिला कर रख दिया और आर्थिक विकास का जो आदर्श स्वरूप (माडॅल) बन रहा था, उसके प्रति भी सर्वसम्मति को इस वित्तीय संकट से धक्का पहुंचा। अब वह वित्तीय संकट निपट गया है और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभावित देशों की अर्थ-व्यवस्थाएं भी अब फिर से पटरी पर आ गई हैं बल्कि कुछ देशों में विकास दर और मजबूत हुई है, जो इन देशों की क्षमताओं का प्रमाण है और साथ ही इस बात का भी प्रमाण है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली उतार-चढ़ावों को झेल सकती हैं।

जैसे ही हम आगे की ओर देखते हैं, हमें एशियाई वित्तीय संकट से जो सबक मिले हैं, उनको भी देखना होगा। अब हमारी समझ आ गया है कि इस वित्तीय संकट के चार बड़े कारण थे-पहला - विनिमय दरें ऐसी थीं, जिन्हें उस स्तर पर हमेशा बनाए नहीं रखा जा सकता था। दूसरा - वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों के कारण उद्यमों ने मुद्रा संरचना की विषमताओं या मैच्योरिटी प्रोफाईल की असंगतताओं को ध्यान में रखे बिना ऋण लिए। तीसरा - नियामक व्यवस्था, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र में नियामक व्यवस्था दोषपूर्ण थी। चौथा - पूंजी निर्गम के स्वरूप और मात्रा पर निगरानी रखने वाली सरकारी व्यवस्थाएं अपर्याप्त थीं ।

वित्तीय संकट के बाद की स्थिति के विश्लेषण से कई मुद्दे सामने आए हैं, जैसे पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए पूर्व शर्ते,स्थिर विनिमय दरें लाभकारी हैं या परिवर्तन शील विनिमय दरें । ये सभी मुद्दे अब मानक स्तरों का रूप ले चुके हैं। इस सब बातों से मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस संकट से हमने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या सबक लिए हैं। इस एशियाई वित्तीय संकट से एक महत्वपूर्ण सबक यही मिलता है कि ऐसे संकट से उबरने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से कारगर, शीघ्र और विश्वसनीय सहायता मिले।

पहला, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्थाओं को बड़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराएं, जिससे उनकी स्थिरता का उन्हें विश्वास हो जाए। आधे-अधूरे उपायों से समस्या हल नहीं होती, बल्कि और बिगड़ जाती है। एशियाई संकट के बाद अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की तुरंत कार्यवाही न करने के लिए काफी आलोचना हुई थी। इस तरह का विचार बन रहा है कि आर्थिक सहायता तुरंत मिलनी चाहिए, न कि तब तक इंतजार किया जाए जब तक कि विदेशी मुद्रा का भंडार खत्म न हो जाए। ये धारणाएं ही हैं जिनके कारण संकट पैदा होता है और तुरंत तथा निर्णायक कार्यवाही से इनको काबू में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए न केवल आर्थिक सहायता की मात्रा, बल्कि कितनी तेजी से यह उपलब्ध कराई जाती है, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण बात है।

दूसरा, एशियाई संकट ने यह दिखा दिया है कि वित्तीय संकट संक्रामक हो सकता है और विदेशी मुद्रा बाजार सामुहिक प्रभाव से अछूते नहीं रह सकते। यह पूंजी बाजार की कमियों का परिणाम है जिसके कारण खबर फैलती है और एक दूसरे की देखा-देखी निवेशकों में आशंकाएं पैदा करती है। आशंकाओं वाली ऐसी परिस्थितियों में पूंजी बाजार देशों के बीच के अन्तर को नहीं देखता और न ही मजबूत और कमज़ोर ढांचों वाली अर्थ-व्यवस्थाओं को देखता है, जिसके परिणाम स्वरूप संकट की चपेट में मजबूत दिखने वाली अर्थ-व्यवस्थाएं भी आ सकती हैं। इसका मतलब है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को आने वाले संकट के प्रति पहले से ही सचेत रहना होगा और उन कमज़ोर अर्थ-व्यवस्थाओं को पहचानना होगा

और समय रहते उनको मदद पहुंचानी होगी, ताकि संकट को टाला जा सके। इसका मतलब यह भी है कि आर्थिक सहायता का आकार बहुत बड़ा रखना होगा ।

तीसरा, अर्थ-व्यवस्था की निरंतर निगरानी और सर्तकता बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए तीन चीजों की जरूरत हैः

- पूंजीबाजार और नियामक व्यवस्थाओं के लिए सूचनाओं के संकलन, निगरानी और प्रेषण की विश्वसनीय प्रणालियाँ।

- आर्थिक प्रबंधन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानक ।

- इन मानकों को लागू करने के लिए सक्षम और प्रभावी नियामक प्रणालियाँ।

संकट के बाद के समय में कई एशियाई देशों ने कई बड़े भंडार बना लिए हैं। हालांकि इन भंडारों से सुरक्षा की पहली पंक्ति ठीक तरह से विकसित हो गई है, लेकिन इससे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की भूमिका कम नहीं हो जाती। इन्हें दुनिया भर की अर्थ-व्यवस्थाओं की गतिविधियों पर निकट से नजर रखनी होगी और विभिन्न देशों को उचित कार्यवाही के बारे में उचित सलाह देनी होगी।

बहनो और भाइयो,

विश्व स्तर पर बढते असंतुलनों को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की भूमिका और भी अधिक संगत हो गई है। विभिन्न देशों के मौजूदा खातों की विशाल असमानताओं से विश्व स्तर पर मौजूद असंतुलन का पता चलता है। वर्ष 2005 में अमरीका का चालू खाता घाटा 805 बिलियन डालर था, जो अमरीका के सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 प्रतिशत है। वर्ष 2005 में ही जापान का चालू खाता अधिशेष 163.9 बिलियन करोड़ डालर था। चीन गणराज्य का अधिशेष 158.6 बिलियन डालर और पश्चिम एशिया के देशों का अधिशेष 196 बिलियन डालर था ।

कुछ हद तक चालू खातों की स्थिति में असंतुलनों की उम्मीद की जा सकती है और यह वांछनीय भी है। लेकिन विश्व अर्थ-व्यवस्था में बड़े स्तर पर असमानताएं इस बारे में चिंता पैदा करती हैं कि अर्थ-व्यवस्था की स्थिति ऐसे नहीं चल सकती, जिससे गहरी आशंकाएं पैदा होती हैं। यदि असंतुलनों को ठीक करने की प्रक्रिया अचानक और अप्रत्याशित होती है, तो यह नुकसानदेह हो सकती है। विश्व स्तर पर असंतुलन की मौजूदा स्थिति को हमेशा के लिए नहीं बनाए रखा जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि मौजूदा खाता अधिशेष वाले देश और खाता घाटे वाले देश दोनों ही कदम उठाएं। स्थिति बिलकुल ही उल्ट न जाए, इसके लिए जरूरी है कि असंतुलनों को ठीक करने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएं। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं इस मामले में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं।

बहनो और भाइयो,

हाल के वर्षों में विश्व व्यापी विकास में हमारे क्षेत्र की भूमिका सक्रिय हो गई है। अमरीका और यूरोप के क्षेत्र विश्व की अर्थ व्यवस्था के विकास में कमोबेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे, लेकिन भारत सहित पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिति निश्चित रूप से सुधरेगी और विश्व की अर्थ-व्यवस्था के विकास में उनका महत्व बढ़ेगा। विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में और विश्व के व्यापार में एशिया का हिस्सा लगातार बढता रहेगा, न केवल निर्यात आपूर्ति के नाते, बल्कि बढते आयात की मांग के नाते भी। एशिया और अधिक खाद्य सामग्री तथा ऊर्जा की खपत करेगा। एशिया में बेहतर बुनियादी ढांचे और बेहतर सुविधाओं की मांग बढ़ेगी। इस क्षेत्र में पूंजी निवेश की बढती मांग को देखते हुए हमें अपनी सामुहिक बचतों का बेहतर उपयोग करने के उपाय ढूंढने चाहिएं। हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो बचत राशियाँ हैं और फालतू धन-राशि है, उसका हम अपने ही क्षेत्र में पूंजी निवेश करें।

एशियाई क्षेत्र में एक दूसरे की सफलताओं से सीखने की भी संभावनाएं हैं। पिछले दो दशकों में चीन की अर्थ-व्यवस्था ने बहुत नाम कमाया है और विकास दर को बढाया है, जिनसे दूसरे देश ईर्ष्या करते हैं। इससे लाखों करोड़ों लोगों को निपट गरीबी के स्तर से ऊंचा उठाने में मदद मिली है। इसके अलावा चीन की अर्थ-व्यवस्था के विकास से अन्य देश के उत्पादों और सेवाओं की मांग बढी है और चीन गणराज्य विश्व अर्थ-व्यवस्था के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। चीन की अर्थ व्यवस्था के इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और एशियाई विकास बैंक इसमें निश्चित रूप से मददगार हो सकता है ।

बहनो और भाइयो,

हमारे क्षेत्र को अन्य चुनौतियों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए, जो हमारे में से अधिकतक देशों के सामने हैं। मैं क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा की चुनौती और समता, सामाजिक न्याय तथा विकास की प्रक्रिया में क्षेत्रीय असंतुलनों की चुनौती का जिक्र करना चाहूंगा ।

हमारे क्षेत्र में सुरक्षा की एक व्यापक व्यवस्था की जरूरत है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके, कि आतंकवाद के खतरे तथा पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और रोजगार की सुरक्षा के लिए पैदा होने वाले खतरों से आर्थिक विकास की प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े। ऐसे समय में,जबकि अन्तर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में लगातार वृद्धि के आसार नजर आ रहे हैं, सभी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वे ऐसी विश्वसनीय नीतियों के निर्माण के लिए अपने सामूहिक ज्ञान, विशेषज्ञता और अनुभव का मिलकर उपयोग करें, जिससे कि विश्व की अर्थ-व्यवस्था, विश्व में ऊर्जा की कीमतों में बढती अनिश्चितता और उतार-चढ़ाव तथा विश्व के आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का मुकाबला कर सके ।

विश्वव्यापीकरण की ओर बढते हुए विश्व में विकास और उन्नति अलग-अलग नहीं रह सकते। विभिन्न देशों और अंतराष्ट्रीय एजेंसियों को कल्याण कार्यों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। एशिया के सामने आज चुनौती है कि वह ऐसा क्षेत्रीय और अन्तर्राट्रीय वातावरण बनाए और उसे कायम रखे, जो सतत् आधार पर उच्च आर्थिक विकास को बनाए रखने में सहायक हो ।

हमारी सरकारों के सामने देश के अन्दर यह सुनिश्चित करने की चुनौती है कि हमारी विकास प्रक्रिया सामाजिक दृष्टि से समतापूर्ण और क्षेत्रीय दृष्टि से संतुलित हो। सामाज के पिछड़े वर्गों की सहायता की जानी चाहिए, ताकि वे विकास में प्रभावी ढंग से भागीदार बन सकें। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आय के अन्तर को कम करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शीघ्र विकास की प्रक्रिया के दौरान पैदा हुए असंतुलनों पर हमें सक्रियता से ध्यान देना होगा और ऐसा सहभागिता वाले लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत किया जाना चाहिए। जैसे-जैसे हम विकास की गति को बनाए रखने के लिए नीतियों को लागू करते हैं वैसे ही हमें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों और समाज के विभिन्न वर्गों को मिलने वाले लाभों में बेहतर संतुलन कायम रहे ।

पिछली चौथाई शताब्दी या इससे कुछ अधिक समय से एशिया एक बार फिर प्रगति के रास्ते पर चल पड़ा है। हमारे क्षेत्र के लाखों लोग गरीबी, अज्ञानता और बीमारी से मुक्त हुए हैं। यदि हम अपनी विकास प्रक्रिया को बनाए रख सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि यह समतापूर्ण हो, तो हम हमेशा के लिए गरीबी को समाप्त कर सकते हैं। यदि हम एक खुली अर्थ-व्यवस्था और एक खुले लोकतंत्रीय समाज के ढांचे में आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम एशिया को वही प्राचीन वैभव दिला सकते हैं जो कभी ज्ञान, बुद्धिमत्ता, सृजनशीलता और करूणा के लिए जाना जाता था।

एशियाई विकास बैंक ने हमारे क्षेत्र में विकास की सोच को नया रूप देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं आपके विचार-विमर्श की सफलता की कामना करता हूं और चाहता हूं कि एशियाई विकास बैंक आने वाले अनेक वर्षों तक हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ सक्रियता के साथ जुड़ा रहे ।

धन्यवाद।

****